बिंदा प्रसाद और अन्य

बनाम

भान दत्त (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि

10 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.]

भूमि कानून और कृषि किरायेदारीः

उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950-एस. 134 और 137-सरदार द्वारा भूमिदारी अधिकारों के लिए आवेदन-जमा अपेक्षित भूमि राजस्व-भूमिधारी अधिकारों की पात्रता प्रभावी तारीखः सिरदारी भूमिधारी का हकदार बन जाता है राशि जमा करने की तारीख से प्रभावी अधिकार एस द्वारा विचार किया गया। 134 धारा 137 के तहत दिया गया प्रमाण पत्र भी संबंधित है। वापस और राशि जमा करने की तारीख से प्रभावी है -तथ्यों के अनुसार, किरायेदार ने सिरदारी के रूपांतरण के लिए निर्धारित किराया जमा किया भूमिधारी अधिकारों में अधिकार और उसी दिन निष्पादित बिक्री विलेख, लेकिन आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मृत्यु हो गई-ऐसे में मामला, किरायेदार की मृत्यु निष्पादित बिक्री विलेख को अमान्य नहीं करेगी सिरदारी भूखंडों के बारे में।

'आर', किरायेदार, ने सिरदारी को बदलने के लिए 20 गुना किराया जमा किया भूमिधारी अधिकारों में अधिकार। उसी दिन आर ने बिक्री निष्पादित की सिरदारी भूखंडों के संबंध में विलेख। हालाँकि, आर की मृत्यु किसी भी घटना से पहले हो गई।सनद या सनद जारी करने के लिए न्यायिक आदेश पारित किया गया था आर के पक्ष में जारी किया गया। निचली अदालतों और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर की मृत्यु तक सनद का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था आर के पक्ष में, भूमिधारी सनद का अनुदान संबंधित नहीं हो सका किराया जमा करने की तारीख तक वापस और हकदार नहीं होगा किराएदार को किराए के 20 गुना जमा करने की तारीख को सिरदारी भूखंडों के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित करना। इसलिए, वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :-

1.1. आवेदन करने पर और भूमि राजस्व का भुगतान किए जाने का निर्धारित समय, सरदार बन जाता है हकदार 'उस तारीख से प्रभावी है जिस दिन राशि दी गई थी एक घोषणा में 'जमा किया गया कि उसने उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिए हैं यू.पी. जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की धारा 137 अधिनियम, 1950। यह खंड स्पष्ट रूप से तारीख निर्दिष्ट करता है। जिस तारीख से अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात जिस तारीख

को धारा 134 द्वारा अनुध्यात राशि जमा की जाती है। यह बात साफ है। समय की अनिश्चितता को नजरअंदाज करता है जब शीर्षक है तारीख को उस तारीख के रूप में तय करके स्थानांतरित किया गया जिस पर राशि जमा की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब आवश्यक रूप से उस तारीख से प्रभावी होना चाहिए जब राशि है जमा किया। धारा की उप-धारा (2) के संशोधन से पहले 137 अधिनियम का यह केवल उप के तहत प्रमाण पत्र का अनुदान था धारा 37 की धारा (1) कि सरदार अपनी तारीख से स्वामित्व का भूमीदार बन गया या माना गया या हिस्सा जिसके संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया था। धारा 137 की उप-धारा 2 का संशोधन धारा 137 (2) लाया गया धारा 134 के अनुरूप। दोनों प्रावधान एक साथ स्पष्ट रूप से पढ़े गए हैं। बशर्ते कि धारा 137 के तहत प्रमाण पत्र कब और कब होगा माना जाता है, यह वापस संबंधित होना चाहिए और तारीख से प्रभावी होना चाहिए जो धारा 134 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशि है। जमा किया गया। [पैरा 8] [11-ए, बी, सी, डी, ई]

देव नंदन और अन्य बनाम राम सरन और अन्य 2000(3) एससी 440 पर भरोसा किया।

1.2. निर्णयों की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय को अलग कर दिया जाता है। [पैरा 9] [12-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं.1579/2001

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.1998 से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) लखनऊ में 1979 की दूसरी सिविल अपील सं. 187।

एस.सी. पॉल, रूपा पॉल, सतविंदर कौर, मोहिंदर सिंह, एस.एस. याचिकाकर्ताओं के लिए मुंडे और रेखा पांडे।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय धारा 100 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज करने को चुनौती दी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') दूसरी अपील प्रतिवादी द्वारा रद्द करने के लिए दायर एक मुकदमे में की गई थी, सिरदारी भूखंडों के संबंध में एक राघोराम द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख। मुकदमा चलाया गया, प्रतिवादी की पहली अपील खारिज कर दी गई। वादी की क्रॉस-आपत्तियों को भी निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था और डिक्री दिनांकित 5.1.1979। दूसरी अपील के खिलाफ निर्देशित किया गया था। निर्णय और डिक्री दिनांकित 20.7.1978 और निर्णय और डिक्री दिनांकित 5.1.1979।

2. रघोराम जो कैंसर के मरीज थे, सितंबर 1979 में उनका निधन हो गया। विवादित भूखंड सिरदारी भूखंड थे और किराए का 20 गुना था। सिरदारी अधिकारों को भूमिधारी अधिकारों में बदलने के लिए जमा 2.8.1976 पर किया गया था और उसी दिन बिक्री विलेख खत्म कर दिया।

3. उच्च न्यायालय के अनुसार जिस बिंदु पर विचार किया जाना था वह था क्या किराए के 20 गुना जमा होने से, रघोराम भूमिधर बन गया ताकि विक्रय विलेख निष्पादित किया जा सके। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु तक कभी-कभी सितंबर, 1979 में न तो कोई न्यायिक आदेश सनद जारी करने के लिए पारित किया गया था और न ही सनद का प्रमाण पत्र जारी किया गया था रघोराम के पक्ष में। यह स्वीकार किया गया कि सनद का अनुदान भूमिधारी अधिकार किराए के 20 गुना जमा करने की तारीख से संबंधित हैं। लेकिन वर्तमान मामले में क्योंकि किसी भी न्यायिक आदेश से पहले किरायेदार की मृत्यु हो गई थी। सनद जारी करने के लिए पारित किया जा सकता है या सनद जारी होने से पहले जारी किया गया, इसलिए, भूमिधारी सनद का अनुदान वापस संबंधित नहीं हो सकता है जमा की तारीख और किरायेदार को बिक्री निष्पादित करने का अधिकार नहीं देगा जमा करने की तारीख को विवादित सिरदारी भूखंडों के संबंध में विलेख 20 किराए का समय। तदनुसार दूसरी याचिका खारिज कर दी गई।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली और उच्च न्यायालय की अदालतें स्पष्ट रूप से इसके विपरीत हैं। 20 गुना किराया जमा करने की तारीख केवल यह तथ्य है कि किरायेदार की मृत्यु हो गई। किसी से पहले उस संबंध में आदेश पारित किया गया था, प्रभाव मिटा दिया जाएगा। बाहर कानून में समर्थनीय नहीं है।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के लिए सीखा हुआ परामर्श आदेश का समर्थन किया।

6. वर्तमान मामले में शामिल प्रश्न से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन की धारा 134 और 137 की व्याख्या और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'अधिनियम')।

7. अधिनियम की धारा 134 और 137 इस प्रकार हैः

> "134 (1) यदि खंड (क) में उल्लिखित वर्ग का कोई सरदार हो। सरकार देय भूमि राजस्व के दस गुना के बराबर राशि या भूमि के लिए आवेदन की तारीख को देय माना जाता है जिस तारीख को राशि जमा की गई है, घोषणा कि उसने धारा में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। 137 ऐसी भूमि के संबंध में"।

जहां तक धारा 137 प्रासंगिक है, वह इस प्रकार हैः

"137 (1) यदि आवेदन विधिवत किया गया है और सहायक कलेक्टर संतुष्ट हैं कि आवेदक घोषणा का हकदार है धारा 134 में उल्लिखित, वह उसे एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। प्रभाव पड़ता है। (2) उप-धारा (1) के तहत प्रमाण पत्र के अनुदान पर सरदार अपनी तारीख से

(अ) स्वामित्व का भूमिधर बनना और माना जाना या वह हिस्सा जिसके संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया है प्रदान किया गया, और

(ख) " * "

8. आवेदन किए जाने और भूमि के निर्धारित समय पर राजस्व का भुगतान किया जा रहा है, सरदार "से प्रभावी" का हकदार बन जाता है। खंड स्पष्ट रूप से उस तारीख को निर्दिष्ट करता है जिससे अधिकार प्रभावी होते हैं। अर्जित किया जाएगा यानी उस तारीख को जिस पर राशि पर विचार किया गया था। धारा 134 द्वारा जमा किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से अनिश्चितता को नजरअंदाज करता है। समय का वह बिंदु जब शीर्षक को तारीख तय करके स्थानांतरित किया जाता है। वह तिथि जिस पर राशि जमा की जाती है। यह महत्वहीन होगा क्योंकि जब धारा 137 के तहत घोषणा की जाती है क्योंकि घोषणा अनिवार्य रूप से उस तारीख से प्रभावी होनी चाहिए जब राशि जमा किया जाता है। धारा 137 की उप-धारा

(2) के संशोधन से पहले धारा 137 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि सरदार अपनी तिथि से स्वामित्व का भूमिधर बन गया या माना जाना है या हिस्सा जिसके संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया है। संशोधन अधिनियम 21 द्वारा धारा 137 की उप-धारा (2) का संशोधन 1962 के 13.12.1962 के प्रभाव से धारा 137 (2) लाई गई धारा 134 के साथ। दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़कर स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है कि जब और जब धारा 137 के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो यह अनिवार्य है वापस संबंधित करें और उस तारीख से प्रभावी हों जिस दिन राशि निर्दिष्ट की गई थी। धारा 134 की उप-धारा (1) में जमा किया गया था। इस संदर्भ में इस न्यायालय का देव नंदन और अन्र बनाम रामसरन और अन्य। [2000 (3) एस. सी. 440] का पैरा 9 उद्धृत किए जाने योग्य व प्रासंगिक है। यह निम्नानुसार देखा गया थाः

> "हमारी राय में, उक्त निर्णय मैदान के विपरीत हैं। धारा 134 और 137 की भाषा और अर्थ समय का प्रासंगिक बिंदु। जब एक प्रमाणपत्र के तहत जारी किया जाता है। धारा 137 वास्तव में उस स्थिति को उस तारीख को मान्यता देती है जब आवेदन किया गया था और भुगतान के तहत विचार किया गया था धारा 134 (1) जमा की गई थी। प्रमाणपत्र, दूसरे शब्दों में, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और यह तारीख से संबंधित होगा आवेदन से। राजस्व को

रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। धारा 134 (1) के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने से अधिकारी दिन इसे प्रस्तुत किया गया था। अतः विधायिका स्पष्ट रूप से यह है कि जब भी कहा जाए। आवेदन स्वीकार किया जाता है और धारा 137 के तहत आदेश पारित किया जाता है। मुकदमे के पक्षकारों की सुनवाई पूरी होने के बाद मृत्यु हो जाती है। और फैसला सुनाए जाने से पहले, मुकदमा कम नहीं होगा। वापस संबंध के सिद्धांत को अनुभागों में शामिल किया गया है। 134 और यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों के 137 अधिनियम।"

9. ऊपर जो कहा गया है उसे देखते हुए अपील की अनुमति है। मुकदमे के फैसलों की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का फैसलाटी और पहले अपीलीय न्यायालय को अलग कर दिया जाता है। लागत आसान हो जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील रणवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।